ब्रिटेन में किएर स्टार्मर के कैबिनेट में 25 मंत्रियों में रिकॉर्ड 11 महिलाएं हैं। इनमें भारतीय मूल की 44 वर्षीय लिसा नंदी को संस्कृति मंत्री बनाया गया है। वह विगान से फिर से चुनकर आई हैं।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:206 दिनांक:07-07-2024 रविवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

गुजरात के सूरत जिले में आज दोपहर सचिन इलाके में एक छह मंजिला इमारत ढह गई। जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं पुलिस और बचाव टीम ने हादसे के बाद मलबे से एक शव बरामद किया है।

23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री

-18वीं लोकसभा का दूसरा सत्रा 22 जुलाई से 12 अगस्त तक

नई दिल्ली(ईएमएस)। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी।

दरअसल, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर टिकी हैं। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत सरकार की संस्तुति पर भारत की माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन)। केंद्रीय बजट 2024-25, 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत

केंद्रीय बजट 2024 की तारीखें घोषित होने के साथ ही, इस बात की काफी उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री मोदी 3.0 सरकार के तहत टैक्सपेयर्स के लिए कुछ लाभों की घोषणा कर सकती हैं। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी।

निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज होगा अनोखा रिकॉर्ड

बता दें कि इस साल दो बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। लेकिन अब नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। इस बार बजट पेश करने के साथ ही वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। कारण, ऐसा करके वह लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इस मामले में वह मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे।

1 फरवरी 2024 को पेश हुआ था अंतरिम बजट

इस साल अप्रैल, मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला ने अपने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्?नदाता, यानी किसान पर फोकस किया था।

पजशकियान ईरान के राष्ट्रपति बने

तेहरान(ईएमएस)। ईरान में मसूद पजशकियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। पजशकियान को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले, जबकि जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट हासिल हुए। पजशकियान डॉक्टर होने के साथ-साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश की करीब 50 प्रतिशत (3 करोड़ से ज्यादा) जनता ने वोट डाला था। आधिकारिक समय के मुताबिक, मतदान शाम 6 बजे खत्म होना था। हालांकि, बाद में इसे रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी।

भारी बारिश के साथ बाढ़ की चेतावनी.... मौसम विभाग ने इन राज्यों को दी

नई दिल्ली (ईएमएस)। एक ओर जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। वहीं, कुछ जगहों पर गर्मी का सितम जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। मौमस विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर भारी बरसात के कारण बाढ़ आ सकती हैं। इन राज्यों में बिहार, असम, मेघालय और रुणाचल प्रदेश में मॉडरेट फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसतरह के हालात बन सकते हैं। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को लेकर भी ऐसा ही अनुमान जाहिर किया गया है।

मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा है कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 7 जुलाई तक जबर्दस्त बरसात हो सकती है। वहीं, उत्तर पूर्वी भारत में नौ से दस जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में छह और 7 जुलाई को हल्की से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में नौ जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, राजस्थान में घने बादल दिखाई दे सकते हैं। इसकारण यहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मानसून की बारिश का कहर...सरकार, नगरीय निकायों के सारे दावों की निकली हवा...

सडक़ों, घरों, स्कूलों, थाना और अस्पताल में भरा पानी

सीवेज सिस्टम फेल... बाढ़ के हालात

-श्योपुर में 13 इंच बारिश, सडक़ पर नाव चलानी पड़ी, घरों और अस्पताल में तीन-चार फीट पानी भरा; मंदिर में संत, घरों में स्टूडेंट फंसे

-अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद

नई दिल्ली/ भोपाल(ईएमएस)। मानसून आते ही शहर से लेकर गांव तक मुसिबतों को पहाड़ टूटने लगा हैं। खासकर शहरों में जन जीवन नारकीय होने लगा है। इसकी वजह यह है कि शहरों का नेटवर्क सिस्टम झमाझम बारिश में पूरी तरह फेल हो जाता है। मप्र, छग, यूपी, राजस्थान के कई शहरों में सीवेज सिस्टम फेल होने के कारण सडक़ों, घरों, स्कूलों, थाना और अस्पताल में पानी भर गया। वहीं जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार को रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल, दोनों रूट पर रुक-रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी।

श्योपुर जिले में देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले के बड़ौदा नगर में पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा पानी गिरा। जिससे सडक़ों, घरों, स्कूलों, थाना और अस्पताल में पानी भर गया। हालात ऐसे बने कि लोग रातभर घरों की छतों पर बैठे रहे। एसडीओपी कार्यालय और थाना तक खाली करना पड़ा। सडक़ों पर इतना पानी भर गया कि यहां नाव चलाकर लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। खाड़ नाला के उफान पर आने से यहां बाढ़ की स्थिति बन गई। श्योपुर का राजस्थान के कोटा और बारां से संपर्क टूट गया। शनिवार को कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया है। रेस्क्यू के लिए एसडीईआरएफ की टीम को बड़ौदा में तैनात किया गया है। उधर, जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार को रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल, दोनों रूट पर रुक-रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। हालांकि शनिवार को बारिश नहीं होने से धीरे-धीरे पानी उतर रहा है। दोपहर करीब 2 बजे बडौदा-कोटा हाइवे से पानी नीचे उतरा। जिसके बाद सुबह से बंद पड़ा आवागमन शुरू हो गया है। नगर में जमा हुआ बारिश का पानी भी निकलने लगा है। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग अपने नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन ने भी सर्वे कराने की बात कही है।

जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग

शिवपुरी जिले में शुक्रवार रात से हुई बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। श्योपुर रोड से छिर्रा जाने वाली सडक़ पर शुक्ला नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। श्योपुर जिले में चंबल, कूनो और पार्वती समेत करीब 15 छोटी-बड़ी नदियां है। बारिश में इनमें बाढ़ आने का खतरा रहता है। इन नदियों के किनारों और आसपास बसे शहर और गांवों में बाढ़ का पानी भर जाता है। बडौदा नगर में खाड़ नाला बाढ़ का कारण बनता है। जिनकी वजह से श्योपुर और बडौदा का राजस्थान से संपर्क टूट जाता है। नदी-नालों के किनारे पर तेजी से हो रहे अतिक्रमण और पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने के कारण भी ऐसी स्थिति बन रही है।

शहरी बाढ़ पूरी तरह से मानव निर्मित

विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी बाढ़ पूरी तरह से मानव निर्मित है, जिसमें खराब रखरखाव वाली नालियां, प्लास्टिक की थैलियां, सिकुड़ती खुली जगहें और जलवायु परिवर्तन भारी बारिश के बाद सडक़ों पर पानी जमा होने में योगदान करते हैं। वर्षा जल संचयन, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध और मौसम पूर्वानुमान का बेहतर उपयोग जैसे कदम बारिश के बाद शहरों में बाढ़ से निपटने में काफी मददगार साबित होंगे। भारत के लगभग सभी मेट्रो शहरों में भारी बारिश ने सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, मुंबई में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। विशेषज्ञों ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की ओर तेजी से पलायन और नागरिक अधिकारियों का उदासीन रवैया सहित कई कारक भारी बारिश के बाद शहरों के ठप होने में योगदान करते हैं। नागरिकों को भी जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्लास्टिक की थैलियां या इस्तेमाल की गई खाने की प्लेटें खुले में या पड़ोस की नालियों में न फेंकी जाएं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ प्रोफेसर वीके शर्मा ने कहा कि शहरों को कचरा संग्रहण और सीवेज निपटान तथा नालियों की नियमित सफाई की उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। यह सच है कि खराब जल निकासी और सीवेज प्रणाली शहरी बाढ़ का असली कारण है। शहरों की ओर पलायन भी होता है, जिससे अक्सर भूमि पर अतिक्रमण होता है और मौजूदा नागरिक बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है। शहरी नियोजन को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए तथा बुनियादी ढांचे को जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अगर नालियों की सफाई ठीक से नहीं की जाती है तो सरकारी अधिकारियों और नगर निगम अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

गर्मी की वजह से अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघला

अनंतनाग (ईएमएस)। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक खबर मिल रही है। ज़्यादा गर्मी की वजह से अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया है। सिर्फ 6 दिन में ही शिवलिंग पिघल गया है। अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। शनिवार को बारिश की वजह से यात्रा रोकी गई है। प्रशासन का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर और ज़्यादा तापमान के कारण बाबा बर्फ़ानी के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई। और सिर्फ 6 दिन में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया। यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी। जो कि 52 दिन चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी।

दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की यात्रा भारी बारिश के कारण दोनों मार्गों पर शनिवार को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात से बालटाल और पहलगाम मार्ग पर रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किये हैं। पिछले साल साढ़े चार लाख लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा में बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शन किए थे।

पेपरलीक गिरोह में गार्गी पुरस्कार विजेता महिला भी शामिल

जयपुर (ईएमएस)। एसओजी की गिरफ्त में आए पेपरलीक गिरोह से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरोह ने एसआई भर्ती के अलावा कई अन्य भर्ती के भी पेपर लीक कराए। असली अभ्यर्थियों की जगह पर डमी कैंडिडेट बैठा कर पेपर दिलाए गए थे।

एक दिन पहले पकड़ी गई छम्मी बिश्नोई गार्गी पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। छम्मी पढ़ने में काफी होशियार थी। इसके कारण नकल गिरोह गैंग ने पैसों का लालच देकर डमी कैंडिडेट बनाने के लिए गैंग में शामिल किया। ओमप्रकाश ढाका पेपरलीक गिरोह के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई का ही गुर्गा है। जगदीश के साथ मिलकर पेपरलीक करवाता है।

गार्गी पुरस्कार ले चुकी, 3 साल में लग्जरी मकान

एसओजी को जांच में पता लगा है कि छम्मी बिश्नोई पढ़ने में शुरू से ही काफी तेज थी। जिले में पहला गार्गी पुरस्कार भी छम्मी को मिला था। शिक्षक भर्ती में वह टीचर बन गई थी। इसके बाद रुपयों के लालच में आकर वह नकल गिरोह गैंग के संपर्क में आ गई। छम्मी डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम में बैठती थी।

शुरुआत में छम्मी 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक लेती थी। बाद में नकल गिरोह से डिमांड बढ़ी तब 10 लाख से भी ज्यादा लेने लग गई थी। इसके बाद में 20 लाख रुपए तक लिए थे।

2021 में छम्मी बिश्नोई डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के लिए गई थी। तभी उसके खिलाफ बालोतरा में मुकदमा दर्ज हो गया था। तब से वह फरार चल रही थी।

नकल के रुपए से डूंगरी गांव में प्लॉट लेकर चार मंजिला लग्जरी मकान भी बनाया था। छम्मी का पति गणपत स्कार्पियो चलाता है। कोई नौकरी भी नहीं करता है। चार मंजिला मकान किराए पर दे रखा है, इसमें ज्यादातर सरकारी टीचर ही रहते हैं। किराए का पूरा लेनदेन खुद गणपत ही करता है।

वृंदावन से किया गिरफ्तार

फरार होने के बाद छम्मी वृंदावन में रहने लगी थी। 6 हजार रुपए में किराए का कमरा ले रखा था। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची थी, तब आरती करती हुई मिली थी। वहीं से पहचान करने के बाद छम्मी को पकड़ा गया था।

हाथरस भगदड़- मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल

कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस, मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर

हाथरस(ईएमएस)। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा था। पुलिस मीडिया से बचने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ाकर बाहर लाई, तभी वह मुंह के बल गिर पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बिठाकर ले गए।

मधुकर और उसके एक अन्य साथी संजीव यादव को अलीगढ़ जेल भेजा गया है। सुबह 11 बजे पुलिस ने मधुकर का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। बाहर निकला तो उसका मुंह अंगौछे से बंधा था। मीडिया कर्मियों ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन देव प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। देव प्रकाश को शुक्रवार रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा कि मधुकर फंड जुटाता था। कुछ समय पहले उससे राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था। अब जांच होगी कि पार्टियों ने फंडिंग तो नहीं की थी। उधर, बिहार के पटना में हादसे को लेकर बीजेपी नेता ने भोले बाबा पर केस दर्ज कराया है। हादसे के बाद शनिवार सुबह पहली बार भोले बाबा सामने आया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा- हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना से बहुत दुखी हैं। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे।

अब खुद का मैप्स यूज करेगी ओला

नई दिल्ली (ईएमएस)। ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। ओला कैब्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। भाविश अग्रवाल ने कहा कि पिछले महीने अजूरे से एग्जिट होने के बाद, अब हम गूगल मैप्स से भी पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं। हम गूगल मैप्स पर सालाना 100 करोड़ खर्च करते थे, लेकिन हमने इस महीने अपने इन-हाउस ओला मैप्स पर पूरी तरह से शिफ्ट होकर उस खर्च को 0 कर लिया है।

केजरीवाल गिरफ्तारी मामले में पत्नी सुनीता का खुलासा

-एनडीए सांसद एमएस रेड्डी का लिया नाम

नई दिल्ली, (ईएमएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि इसके पीछे उनका ही हाथ है। उनका कहना था कि सीएम केजरीवाल गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं, गवाह के झूठे बयान पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस आशय का संदेश उन्होंने वीडियो क्लिप के जरिए दिया है।

वीडियो मैसेज जारी करते हुए सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि क्या आप को पता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है? उनकी गिरफ्तारी एनडीए के सांसद के बयान पर की गई है। उनका नाम मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी यानी एमएसआर है। गौरतलब है कि एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के सांसद हैं। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि एनडीए के सांसद मंगुटा रेड्डी ने ईडी को पहले दो बार जो बयान दिए, वह ईडी को पसंद नहीं आए। इसके बाद ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया और पांच महीने तक जेल में प्रताड़ित किया। बेटे और परिवार की हालत देख सांसद मंगुटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया और ईडी जो चाहती थी, वह अपने बयान में बोल दिया। इसके बदले में मंगुटा रेड्डी के बेटे को जमानत दे दी गई। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि सांसद मंगुटा रेड्डी ने ईडी के समक्ष झूठा बयान दिया था। दावा किया जा रहा है कि सांसद ने खुद कहा था कि उनकी 16 मार्च, 2021 को अरविंद केजरीवाल से पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या पहली बार में ही कई लोगों के सामने पैसे मांग सकता है? सुनीता केजरीवाल के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरु हो जाएगा। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को राजनैतिक षडयंत्र का शिकार बनाया गया है। ऐसे समय में हमें उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है।

पटना में भोले बाबा के खिलाफ केस दर्ज

पटना(ईएमएस)। यूपी के हाथरस कांड को लेकर सूरज पाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ पहला केस पटना में दर्ज कराया गया है। पटना के सिविल कोर्ट में सूरज पाल सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने केस दर्ज कराया है। सिविल कोर्ट के वकील रवि रंजन दीक्षित ने कहा कि हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर पहला केस पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ है। इसका केस नंबर 8438/24 और फाइलिंग नंबर 97/95 है। केस निचली अदालत में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109, 114 115, 303, 304 के तहत फाइल कराया गया है। केस दर्ज होने के बाद गवाही होगी और जब तक सजा नहीं होगी तब तक कोर्ट में मामला चलता रहेगा।

केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला

14 साल का लडक़ा संक्रमित, 3 बच्चों की मौत; नाक के जरिए शरीर में घुसता है

कोझिकोड (ईएमएस)। केरल में इंसानी दिमाग खाने वाले अमीबा का एक और केस मिला है। एक 14 साल के लडक़े में रेयर ब्रेन इन्फेक्शन अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। लडक़े का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, ब्रेन इन्फेक्शन से पीडित लडक़ा उत्तरी केरल जिले के पय्योली का रहने वाला है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 1 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। उसे विदेश दवाएं दी गईं। अब उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। केरल में मई से अब तक दिमाग खाने वाले अमीबा के चार केस मिले हैं। सभी मरीज बच्चे हैं, जिनमें से तीन की पहले ही मौत हो चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह संक्रमण तब होता है जब फ्री-लिविंग गैर-परजीवी अमीबा बैक्टीरिया दूषित पानी से नाक के जरिए शरीर में घुसता है।

बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते: आरबीआई

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक नोट नहीं बदलता है, तब इसकी शिकायत की जा सकती है। यस बैंक को भी अब कटे-फटे नोट बदलने से इंकार करना महंगा पड़ा है। आरबीआई ने यस बैंक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यस बैंक ने बाजारों को दी जानकारी में बताया कि यह दंड कटे-फटे नोट नहीं बदलने पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक को भेजे पत्र में बताया कि आरबीआई अधिकारियों के एक शाखा में दौरा करने के दौरान कटे-फटे नोट नहीं बदले जाने के प्रमाण मिले थे।

आरबीआई के सख्त दिशानिर्देश हैं कि बैंकों को खराब नोटों को बदलना होगा। वे ऐसा करने से इंकार नहीं कर सकते हैं। 10 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी कटे-फटे नोट को बैंक में बदला जा सकता है। बशर्ते कि उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा भाग मौजूद हो और नोट का पहचान नंबर साफ दिखाई दे रहा हो। सरकारी और निजी बैंक या आरबीआई इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे ही नोट बदले जा सकते हैं।

आरबीआई ने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.32 करोड़ रुपये का दंड लगाया। यह दंड लोन, उधारी और केवाईसी मानदंडों को पूरा नहीं करने पर लगाया गया है।

हाथरस हादसा: बाबा भोले ने हादसे को साजिश करार दिया

मैनपुरी (ईएमएस)। यूपी के हाथरस जिले में हुई भगदड़ के बाद सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि पहली बार मीडिया के सामने आया है। बाबा ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा है कि दो जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूं। बाबा ने कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। सूरजपाल उर्फ 'भोले बाबा' ने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने कहा कि मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। सूरजपाल ऊर्फ भोले बाबा ने कहा कि पीड़ितों की मदद करूंगा। मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ हूं। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया।

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा - प्रदेश सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करे

रांची (ईएमएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करके उन्हें वापस भेजने के लिए कार्ययोजना तैयार करें।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की पीठ ने 3 जुलाई 2024 को डानियल दानिश की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए। याचिका में अदालत को बताया गया था कि संताल परगना जैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की जनजातीय लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है।

इसमें ये भी कहा गया था कि संताल परगना के बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में भी बढोतरी हुई । नए 46 मदरसे हैं। याचिका में कहा गया कि इन मदरसों के जरिए देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। न केवल जनजातीय महिलाओं का शोषण हो रहा है बल्कि घुसपैठिए जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि इन मदरसों के जरिए देश में देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है, साथ ही साथ ये घुसपैठिए, जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं।

अदालत ने इस मामले में सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें उन्हें बताना है कि उन्होंने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित किया, कितनों को रोका और कितनों को वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है।

राहुल गांधी 8 जुलाई को जा सकते हैं मणिपुर, विस्थापितों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली,(ईएमएस)। मणिपुर संकट से निपटने और समाधान के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी ने 8 जुलाई को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान राज्य के सीएसओ नेताओं से मिलेंगे और चुराचांदपुर, मोइरांग और अन्य स्थानों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा विपक्ष के नेता के रूप में देश में उनकी पहली यात्रा होगी। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपनी नीतियों और राजनीति के कारण मणिपुर को गृहयुद्ध में धकेलने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस नेता ने जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का दौरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है मानो मणिपुर भारत का राज्य नहीं है। हमने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे संदेश दें, वहां जाएं. लेकिन कोई नहीं गया। आपको जवाब नहीं मिल सकता।

राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं की दुर्दशा का भी जिक्र किया। सत्तापक्ष की एक टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने संगठन में महिलाओं को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बोल सकता हूं। मणिपुर पिछले साल मई से हिंसा की चपेट में है क्योंकि घाटी के प्रभुत्व वाले मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में कुकी आदिवासियों द्वारा आयोजित एक मार्च के बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी।

वायकर का मामला बंद करना, शिंदे सरकार ब्लैकमेल नीति का उदाहरण : कांग्रेस

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने के महीनों बाद, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लक्जरी होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए उनके खिलाफ मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। वायकर वर्तमान में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों के मामूली अंतर से हराया। एक समय उद्धव के करीबी सहयोगी रहे वायकर मार्च 2024 में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए। वह बृहन्मुंबई नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष, चार बार पार्षद और जोगेश्वरी से चार बार विधायक रहे। वे 2014 और 2019 के बीच आवास, उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री थे।

वायकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार, उन्होंने जोगेश्वरी में एक भूखंड पर खेल सुविधा चलाने की

जन हितैषी

लोकसभा में नीट मामले पर चर्चा क्यों नहीं

18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था। विपक्ष चाहता था कि 24 लाख नीट के विद्यार्थियों पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष ने इसको स्वीकार नहीं किया। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में नीट मामले की याचिकाएं विचाराधीन होने की आड़ में सरकार नीट मामले में सदन के अंदर चर्चा करने से बचती रही। संसद एक ऐसा मंच है। जहां पर सांसद किसी भी बात को निष्पक्षता और निडरता के साथ रख सकते हैं। सदन के अंदर सांसद न्यायपालिका और न्यायाधीशों के संबंध में भी अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही होती है, उस पर जरूर कोई टीका-टिप्पणी सांसद नहीं करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष की सहमति से सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में सदन के नियमित कामकाज को स्थगित करके चर्चा कराए जाने का प्रावधान है। पहले भी सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती रही हैं। नीट मामले में 24 लाख परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। 100000 युवाओं का एडमिशन एमबीबीएस में होना है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कराया जाना, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों से मुह मोड़ने के समान है। इस मामले में यदि लोकसभा में चर्चा होती तो निश्चित रूप से सरकार को इसका फायदा होता। सरकार के खिलाफ अभी पेपर लीक मामले और नीट के मामले में युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है। यदि चर्चा हो जाती, आम सहमति से सदन में कोई सहमति बनती। इससे युवा वर्ग के घाव पर मलहम लगाने जैसा उपचार होता। सरकार ने सदन में नीट मामले में चर्चा नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र सरकार ने प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है, कि नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिसके कारण परीक्षा कैंसिल करनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नीट को लेकर जो पक्ष रखा है। युवाओं के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। यही बात संसद के अंदर चर्चा में आती। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखते। सरकार जिस आधार पर कह रही है, कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। संसद के माध्यम से वह बात सारे देश में पहुंचती। इससे युवाओं में जो नाराजी है, वह कम होती। युवाओं को लगता सदन में उनकी बात सुनी गई है।

न्यायपालिका की आड़ लेकर पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर संसद में चर्चा नहीं कराई जा रही है। पहले भी कई मामलों में यह देखा जा चुका है। पैगासस, राफेल और हिडेनबर्ग जैसे मामले में सदन में चर्चा नहीं कराई गई। न्यायपालिका में विवाद को डाल दिया गया। न्यायपालिका की आड़ लेकर सरकार हमेशा अपना पक्ष रखने से बचती रही है। सरकार ने न्यायालय में सील बंद लिफाफे में जानकारी देने की नई परंपरा शुरू की। न्यायालय से सरकार ने अपने पक्ष में निर्णय भी प्राप्त कर लिया। इसको लेकर न्यायपालिका और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास में कमी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष किया है। उन्होंने न्यायपालिका को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने यहां तक कह दिया, प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। इसी तरह न्यायालयों से न्याय होगा या अन्याय होगा। जिस तरह से न्यायालय में आधे-अधूरे निर्णय दिए जा रहे हैं। विपक्ष के बारे में न्यायपालिका की भूमिका कुछ और है। सत्ता पक्ष के बारे में न्यायपालिका की भूमिका कुछ और है। उन्होंने सदन के अंदर न्यायपालिका के जजों की कार्यप्रणाली पर प्रत्यक्ष हमला किया है। वर्तमान केंद्र सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। विपक्ष अब आक्रामक मुद्रा में है। न्यायपालिका को भी अपनी साख बचा कर रखना जरूरी हो गया है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में सरकार न्यायपालिका की आड़ लेकर ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकती है। वर्तमान स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्ष और सभापति की जिम्मेदारी है। संवेदनशील मामलों में, जैसे नीट, मणिपुर, बजट और संसद में जो भी कानून बने, उन सब में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा कराई जाए। इससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लिए जा सकेंगे। निर्णय अच्छे होंगे और सभी को जोड़कर रख सकेंगे। संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बैरभाव बना हुआ है। उसमें समन्वय बनाने का काम पीठासीन अधिकारियों को ही करना होगा।

बिहार में पूल क्यों ढह रहे हैं?

हाल ही में जिस तेजी से पुल ढह रहे हैं, उससे पुल निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में कमी का संकेत मिलता है। मानसून के मौसम में पानी के तेज़ बहाव के कारण पुल खराब हो रहे हैं। नए पुल में गुणवत्ता की कमी है और पुराने पुल की कभी मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। पुल एक जटिल ओवरपास संरचना है, जिसमें पुल के डेक, गर्डर, पियर्स और बियरिंग जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं जो यातायात को नदियों, घाटियों, निचली भूमि या सड़कों से गुजरने में सक्षम बनाते हैं।

डिज़ाइन और निर्माण तकनीक में प्रगति के साथ, पुल की संरचनाएँ बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन वे अभी भी निर्माण के दौरान या कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्षतिग्रस्त होने की चपेट में रहने से हैं।परिवहन नेटवर्क में पुल सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक हैं। कोई नहीं जानता कि पुलों की अवधारणा वास्तव में कैसे शुरू हुई, लेकिन प्रारंभिक मनुष्यों ने भौगोलिक बाधाओं को पार करने के लिए गिरे हुए पेड़ों, सीढ़ियों के पत्थरों और अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सामग्रियों का उपयोग किया। प्रबलित का उपयोग संभवतः 1870 के दशक में शुरू हुआ जब लोहे को एम्बेडेड किया गया था, लेकिन 20वीं सदी के पहले दशक तक सुदृढीकरण, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं, पेश नहीं किया गया था। फिर सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए उनमें सुधार किया जाता है। नतीजतन, अचानक ढहने से काफी नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पुल की संरचनाएँ कठोर बाहरी परिस्थितियों के संपर्क में रहती हैं, जिससे वे क्षतिग्रस्त होने और अचानक ढहने की संभावना बढ़ती हैं। इसलिए, विनाशकारी सुरक्षा निरीक्षणों के माध्यम से प्रत्येक पुल की स्थिति और सुरक्षा स्तर का नियमित रूप से आकलन करना आवश्यक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रबलित कंक्रीट पुलों में पोस्ट-टेंशनिंग बल में कमी से टेंडन में शेष बल का अनुमान लगाने में चुनौतियाँ आती हैं। पीज़ोइलेक्ट्रिक पैच का उपयोग अवशिष्ट पोस्ट-टेंशनिंग बल का अनुमान लगाने की एक विधि है।

इसमें एंकर लॉक पर दो पैच लगाना और फिर आठ चरणों में टेंडन को टेंशन देना शामिल है। प्री-टेंशनिंग और पोस्ट-टेंशनिंग कंक्रीट पुलों में टेंडन पर तनाव लगाने के दो तरीके हैं, जिसमें एंकरेज सिस्टम जैसे कि वेज, बेयरिंग प्लेट और ग्राउट कनेक्शन तनाव को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन घटकों की निगरानी तनाव बलों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। तन्यता बल को मापने के पारंपरिक तरीके, जैसे कि प्रकाश परीक्षण, समय लेने वाले और महंगे हैं। ब्रिज की प्राकृतिक आवृत्ति और तनाव बल के बीच संबंध स्थापित करने से कंपन विश्लेषण के माध्यम से तनाव बल का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। लोचदार बल, लोचदार तरंग वेग और लोचदार मापांक के बीच एक संबंध है, जो दर्शाता है कि लोचदार बल में वृद्धि के साथ तरंग वेग गैर-रैखिक रूप से बढ़ता है। पुल का डिज़ाइन बनाते समय, केवल निर्मित पुल के व्यवहार और साइट पर विशिष्ट ट्रैफ़िक का पूर्वानुमान लगाया जाता है ।

लोड और प्रतिरोध कारक डिज़ाइन विनिर्देश हैं, जो कठोरता और ताकत के कई माध्यमिक स्रोतों की उपेक्षा करते हैं। पुलों का डिज़ाइन बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लोड के दौरान पुल की निगरानी करना ट्रैफ़िक पर डेटा एकत्र करने के लिए सबसे अच्छा मॉडल प्रदान करता है ब्रिलौइन ऑप्टिकल टाइम डोमेन एनालिसिस (ँ्रूऊँ) सेंसिंग तकनीक अत्यधिक क्वांटाइज्ड कंसेंट्रिक बीम में गर्मी के नुकसान की व्यापक निगरानी को सक्षम बनाती है।धारा के किनारे वैकल्पिक स्थलों पर मिट्टी और उप-मिट्टी की स्थिति भिन्न हो सकती है। तकनीकी व्यवहार्यता के अलावा, सौंदर्य और लागत जैसे कारक भी साइट के चयन में भूमिका निभा सकते हैं। समाज के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर डिज़ाइन प्रदान नहीं किए जाते हैं, जहाँ कई विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं और साइट अक्सर नियमित होती है। साइटों के विकल्पों को नियोजित या अनियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आदर्श विशेषताओं वाली साइटें, जैसे कि नदी तक सीधी पहुँच, दृढ़ तट, उच्च बाढ़ के स्तर के लिए उपयुक्त उच्च स्तर के तट और सीधी सड़क संरेखण के निकट चुनी जाती हैं। नदी के तल के पास चट्टानों या कठोर अपरदनशील परतों, आर्थिक विचार, मोड़ की अनुपस्थिति, नदी प्रशिक्षण कार्यों और अतिरिक्त जल संचय से बचने की क्षमता जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।निर्माण संबंधी गलतियों, हाइड्रोलिक समस्याओं, टकरावों और अतिभार के साथ-साथ डिजाइन संबंधी खामियां भी पुल की विफलता का प्रमुख कारण हो सकती हैं।

(लेखक- संजय गोस्वामी/ ईएमएस)

गांवों से पलायन एवं बढ़ते शहरीकरण के खतरे

भारत में बढ़ता शहरीकरण भले ही विकास का आधार हो, लेकिन इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। बढ़ता शहरीकरण केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिये एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगी है। गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने एवं नया भारत-विकसित भारत बनाने के लिये शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। एक विडम्बनापूर्ण सोच देश के विकास के साथ जुड़ गयी है कि जैसे-जैसे देश विकसित होता जायेगा वैसे-वैसे गांव की संरचना टूटती जायेगी। निश्चित ही जब भी शहरों में कोई नई कॉलोनी विकसित होती है तो हमें यह स्वीकारना ही होगा कि किसी न किसी गांव की कुर्बानी हुई है। एक और विडम्बना एवं त्रासदी है कि जिन्हें शहर कहा जा रहा है वहां अपने संसाधना से वंचित लोगों की बेतरतीब, बेचैन और विस्थापित भीड़ ही होगी।

कुछ समय पूर्व स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढाँचों में सुधार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाये जाने की अपेक्षा है। वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गाँवों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश, पर्यावरण की समस्या, बढ़ता प्रदूषण, जल का अभाव एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंधमूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गाँवों की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रदूषण का एक-दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? बेहतर रोजगार, आधुनिक जनसुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर-बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या लगभग 350 हो गई है जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांवों की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। यह भी सच है कि ये सुविधाएं सभी को नसीब भी नहीं होतीं। रोजगार के लिए गांवों से शहरों में आने वाले बहुत सारे लोगों को कच्ची बस्तियों, चालों या एक से दो कमरें के मकानों में किराए पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शहरों में रहना दूभर ही होता जा रहा है। असल में देखें तो संकट वायु प्रदूषण का हो या जंगल का, स्वच्छ वायु का हो या फिर स्वच्छ जल का, सभी के मूल में विकास की वह अवधारणा है जिससे शहर रूपी सुरसा सतत विस्तार कर रही है और उसकी चपेट में आ रही है प्रकृति और उसकी नैसर्गिकता। जिसके कारण मनुष्य की सांसें उलझती जा रही है, जीवन पर संकट मंडरा रहा है। अगर हमें पूरी समस्या से लड़ना है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित महानगरों के स्तर पर और साथ ही पूरे देश के स्तर पर अपनी कई आदतों को बदलना होगा, विकास के तथाकथित मॉडल पर गंभीर चिन्तन करना होगा। वायु प्रदूषण का कारण पराली एवं सड़क पर दौड़ते निजी वाहनों में खोजने की बजाय हमें महानगरों के अनियोजित शहरीकरण में खोजना होगा।

पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि शहर के विकास के लिये हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा, तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिये खतरा बन गया है क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियाँ बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिये यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं।

शहर के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए और दफ्तर चाहिए। इन सबके लिए या तो खेत होम हो रहे हैं या फिर जंगल। जंगल को हजम करने की चाल में पेड़, जंगली जानवर, पारंपरिक जल स्रोत सभी कुछ नष्ट हो रहा है। यह वह नुकसान है जिसका हर्जाना संभव नहीं है और यही वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। शहरीकरण यानी रफ्तार और रफ्तार का मतलब है वाहन और वाहन है कि विदेशी मुद्रा भंडार से खरीदे गए ईंधन को पी रहे हैं और बदले में दे रहे हैं दूषित वायु। शहर को ज्यादा बिजली चाहिए यानी ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा परमाणु संयंत्र लगेंगे। शहर का मतलब है औद्योगिकीकरण और अनियोजित कारखानों की स्थापना, जिसका परिणाम है कि हमारी लगभग सभी नदियां अब जहरीली हो चुकी है। महानगरों की बढ़ती आबादी को सिर छुपाने को मकान चाहिए, जिसके लिये हरीतिमा क्षेत्रों को हम कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते जा रहे हैं। नदी थी खेती के लिए, मछली के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, न कि उसमें गंदगी बहाने के लिए। गांवों के कस्बें, कस्बों के शहर और शहरों के महानगर में बदलने की होड, एक ऐसी मृग मरीचिका में लगी है, जिसकी असलियत कुछ देर से खुलती है लेकिन जब खुलती है तब तक लोगों की सांस लेना दुभर हो चुका होता है, जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं।

दरअसल स्वतन्त्र भारत के विकास के लिए हमने जिन नक्शे कदमों पर चलना शुरू किया उसके तहत बड़े-बड़े शहर पूंजी केन्द्रित होते चले गये और रोजगार के स्रोत भी ये शहर ही बने। शहरों में सतत एवं तीव्र विकास और धन का केन्द्रीकरण होने की वजह से इनका बेतरतीब एवं असंतुलित विकास स्वाभाविक रूप से इस प्रकार हुआ कि यह राजनीतिक दलों के अस्तित्व और प्रभाव से जुड़ता चला गया, लेकिन पर्यावरण एवं प्रकृति से कटता गया। प्रबुद्ध नागरिक बढ़ते शहरीकरण को लेकर चिंतित रहते हैं और अनियोजित शहरी विकास को नियोजित विकास का रूप दिलाने के लिए न्यायालयों तक का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके बावजूद अनियोजित शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण के दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे हैं। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। शहरों के विस्तार की बजाय गांवों-कस्बों के विकास पर ध्यान देना होगा। गांव आधारित आर्थिक विकास एवं आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना होगा। वहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करके ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर पलायन से रोका जा सकता है। इससे शहरों पर दबाव भी कम होगा और पर्यावरण, स्वास्थ्य, जीवनशैली पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में भी कुछ हद तक कमी आएगी।(लेखक- ललित गर्ग/ ईएमएस)

नेपाल और इंग्लैंड में सरकारों का पतन

भारत में भाजपा गठबंधन की सरकार जैसे-तैसे बच गयी लेकिन पड़ौस में नेपाल और इंग्लैण्ड की सरकारें गिर गयी । नेपाल में सरकार बैशाखी हटने से गिरी जबकि इंग्लैंड में जनादेश से। दुनिया में सरकारों का बनना,बिगड़ना एक सनातन प्रक्रिया का अंग है ,लेकिन इनके बनने-बिगड़ने का असर आस=पड़ोस पर भी पड़ता ही है। भारत के साथ भी यही फार्मूला लागू होता है। इसलिए भारत और भारतवासियों को इन घटनाओं पर नजर रखना पड़ती है ।

सबसे पहले बात नेपाल की करें। यहां प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' की सरकार थी । बैशाखियों पर टिकी ये सरकार आखिर गिर गयी। सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी सीपीएन-यूएमएल ने प्रचंड को हटाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी (नेपाली कांग्रेस) के साथ सत्ता-साझेदारी समझौते के बाद समर्थन वापस ले लिया है.अब यहां केपी शर्मा ओली के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। शर्मा जी भारत के नहीं चीन के समर्थक हैं । इसलिए भारत को शर्मा जी के आने से परेशानी होना स्वाभाविक है। नेपाल में पिछले 16 साल में 13 सरकारें गिरीं हैं ,नेपाल की सरकारों के गिरने की कहानी अलग है। अभी तो हम प्रचंड के जाने और ओली के आने की बात कर रहे है।

नेपाल में हमारे कुछ साहित्यिक मित्र हैं जो बताते रहते हैं की प्रचंड ने भारत की तर्ज पर नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने की दिशा में काफी काम किया । भारत में राम लाला की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर नेपाल में भी एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गयी । दीपावली मनाई गयी ,लेकिन राम जी नेपाल सरकार के काम नहीं आये । प्रचंड को आखिर जाना ही पड़ा ,दुनिया में धर्म की राजनीति ज्यादा नहीं चलती । वहां भी जहाँ धार्मिक आधार पर ही चुनाव होते है। बहरहाल हमें शर्मा जी के जाने और ओली जी के आने पर सतर्क रहने की जरूरत है ,क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है । हमारी सरकार के सहयोगी दल भी कब अपनी बैशाकहियाँ हटाकर मोदी जी को प्रचंड जैसा असहाय कर दें कोई नहीं जानता।

अब चलिए इंग्लैंड। यहाँ भारत के कथित दामाद ऋषि सुनक की सरकार थी। ताजा चुनाव में इंग्लैंड की जनता ने सुनक की पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया । इस परिवर्तन में भारतवंशियों तक ने सुनक साहब का साथ नहीं दिया। सुनक को भारत की सरकार भारत का दमाद मानती थी। मानना ही चाहिए। हमारे यहां गांव-गोंड़े के रिश्ते बहुत चलते हैं। लेकिन सुनक साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए न भारत के लिए बहुत कुछ किया ,और न भारतवंशियों के लिये । नतीजा ये हुआ कि उन्हें अब सत्ता से बाहर जाना पड़ा। सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर उनके भारतवंशी होने को लेकर कभी कोई विवाद नहीं उठा ,अन्यथा वहां कोई गुजराती प्रतिद्वंदी होता तो उन्हें श्यामा गाय का बछड़ा कह सकता था। हमारे यहां तो इटली मूल की भारतीय बहू को जर्सी गाय और बारबाला कहने वाले अनेक विद्वान हैं।

बहरहाल ब्रिटेन में चार जुलाई को हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है. कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है. लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी तथा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ ही पारस्परिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक व रचनात्मक सहयोग की उम्मीद जताई. मोदी जी ने इसके साथ ही निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके 'सक्रिय योगदान' के प्रति आभार जताया।

भारत के आसपड़ोस में श्रीलंका है ,पकिस्तान है ,चीन है इन सबसे हमारे रिश्ते कैसे हैं ,ये बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से हमारी कुट्टी हुए अरसा हो चुका है । चीन को हम साबरमती में झूला झूला चुके हैं ,लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। पकिस्तान की फितरत तो बदलने का सवाल ही नही। श्रीलंका भी चीन के प्रभाव में है । उसके ऊपर हमारा प्रभाव न जाने क्यों नहीं पड़ रहा। श्रीलंका वाले तो हमारे मोदी जी के शपथग्रहण समारोह में भी नजर नहीं आये। जो पड़ौसी आये थे उनमें से मालदीव वाले भी मन मारकर आये थे। ये सारे सन्दर्भ में इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आसपास की राजनीतिक गतिविधियां भारत के अनुकूल नहीं हैं।

भारत में नेपाल जैसी ही गठबंधन की सरकार है। हमारी कामना और प्रार्थना है कि ये सरकार पूरे पांच साल चले,क्योंकि भारत जैसा गरीब देश दो-ढाई साल में चुनाव की मार सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारी कामना और प्रार्थना से बात बनने वाली नहीं है । ये सरकार तो नायडू,नीतीश बाबू , जलते-बुझते चिराग और जीतनराम माझी के भरोसे चलने वाली सरकार है । जिस दिन भी इन छुटभैयों का माथा सटका उस दिन सरकार को प्रचंड गति मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी सरकारें अक्सर हिकमत अमली से चलती हैं। पीव्ही नरसिम्हाराव ,अटल बिहारी बाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह ने ऐसी सरकारें बाखूबी चलकर दिखाई । किन्तु माननीय मोदी जी के लिए ऐसा करना शायद कठिन हो। क्योंकि वे न राव हैं ,न बाजपेयी हैं और न मनमोहन सिंह। वे मोदी जी हैं,नरेंद्र दामोदर मोदी। उनकी चाल,चरित्र और चेहरा बदलना आसान काम नहीं है।उनका एजेंडा हिडन नहीं है,खुल्लम-खुल्ला है। वे भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्योंकि आरएसएस ऐसा चाहता है। वे मजबूर हैं। वे भारत की विविधता ,धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। वे मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं मानते । उनके लिए मणिपुर भारत का कोई राज्य नहीं है।

कुल जमा हमारे लोग ब्रिटेन में भी हैं और नेपाल में भी। इसलिए हमें यहां हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अपनी विदेश नीति की भी समीक्षा करना पड़ेगी । आने वाले दिनों में अमेरिका में भी चुनाव होना है हमें सबको साथ लेकर इस मसले पर संसद में संसद के बाहर चाय पीते हुए भी बात करना पड़ेगी ,अन्यथा हमारे लिए यानि भारत के लिए, नयी समस्याएं खड़ी हो सकतीं हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बैशखियों पर टिकी सरकार इस मामले में गाम्भीर्य का प्रदर्शन करेगी। नहीं करेगी तो सरकार के साथ-साथ पूरे देश को इसका खमियाजा भुगतना पडेगा।सरकार कि मुखिया का या है ,वे तो फकीर हैं ,लेकर अपना झोला झंडा चल पड़ेंगे। (लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

आज का इतिहास 7 जुलाई

1763 मीर जाफर दोबारा बंगाल के नवाब बने.
1801 हैली ने फ्रांस से स्वतंत्र होने की घोषणा की.
1815 नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा गद्दी छोड़ने पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पेरिस पहुंची.
1896 भारत में सिनेमा पहली बार फ्रांस से आया जब मुंबई के वाटसन होटल में फिल्म दिखाई गई.
1898 अमरीका ने हवाई पर अधिकार कर लिया.
1913 ब्रिटिश संसद ने आयरिश होम रूल्स विधेयक पारित किया.
1925 दक्षिण अफ्रीकी सीनेट ने रंगभेदी विधेयक को ठुकरा दिया.
1937 चीन जापान युद्ध भड़का.
1943 रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी.
1948 दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई.
1960 बेल्जियम ने कांगो में अपनी फौजें भेजी.
1973 सरकार का तख्ता पलटने के आरोप में इराक में 23 व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई.
1989 बर्मा में लाखों लोगों ने मार्शल- लॉ का उल्लंघन कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया.
1991 जार्डन के शाह हुसैन ने मार्शल- लॉ के प्रावधानों को समाप्त कर दिया.
1994 यमन में दो माह से जारी गृहयुद्ध समाप्त हुआ.
2002 भारत ने अल जजीरा के संवाददाता नासिर एम. शहीद को एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ कर चले जाने का आदेश दिया.
2002 हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल का देहांत हो गया, वे 73 वर्ष के थे.

शब्द पहेली - 8060

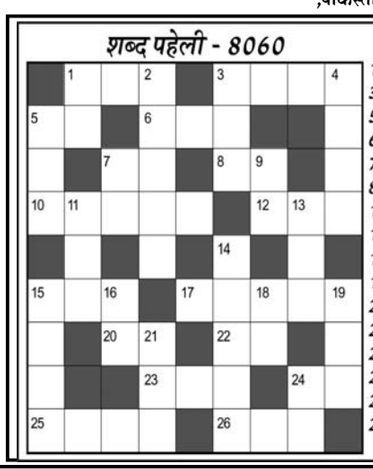

बाएँ से दाएँ

1.सुगंध,खुशबू-3
3.व्यवस्था-2,2
5.आम लोग-2
6.चिंतन,सोच विचार-3
7.पराया-2
8.विनाश,विध्वंस-2
10.अपने ही घर में बंधक-5
12.वसय,घेरा-3
15.आंचल,पल्लू-3
17.सेंधमार-5
20.भाग्य (अंग्रेजी-2)
22.एक सवारी गाड़ी-2
23.पीहर,पिता का घर-3
24.नवीन,नया,नवजात-2
25.लात मारना-4
26.जोंक,न भरने वाला जख्म-3

ऊपर से नीचे

1.जी,चित्त,इच्छा-2
2.करधनी,कमर में पहना जाने वाला आभूषण-5
3.तार कसना-3
4.जोकर,विदुषक-4
5.दुनिया,जगत-3
7.पंख-2
9.सदैव,हरदम-2
11.जन्म,पैदा होना-3
13.जुड़वा-3
14.आश्चर्य में पड़ना-5
15.जंगल की आग-4
16.टोंटी,नलका-2
18.वश,अधीन-2
19.परिणाम,हल-3
21.अर्जित करना-3
24.लोहे की तांत-2

शब्द पहेली -8059 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचे स्पेन और फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल बाहर

अंतिम मैच में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाये रोनाल्डो

स्टटगार्ट (ईएमएस)। स्पेन ने यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में मेजबान जर्मनी को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। स्पेन की ओर से विजयी गोल अतिरिक्त समय में मिकेल मेरिनो ने किया। इसी के साथ ही मेजबान जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। इसी के साथ ही स्पेन की टीम छठी बार यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। दोनों ही टीमें तय समय तक 1-1 से बराबरी पर थीं। जिसके बाद अतिरिक्त समय दिया गया जिसमें मेरिनो ने गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस मैच में स्पेन की टीम हावी रही।

वहीं हैम्बर्ग में खेले गये यूरोकप के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पुर्तगाल को पैनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया। इसी के साथ ही पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरो कप से जीत के साथ विदाई लेने का सपना टूट गया। रोनाल्डो ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी यूरो कप होगा। रोनाल्डो ने रिकॉर्ड छह बार यूरो कप में हिस्सा लिया! उनके नाम दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड है। इस मैच में भी दोनों टीमें अतिरिक्त समय तक एक भी गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। इसमें पुर्तगाल के जोआओ फेलिक्स का शॉट गोल पोस्ट से टकरा गया। इसके बाद थियो हर्नांडेज ने निर्णायक किक को गोल में बदलकर फ्रांस को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।

विंबलडन : भारत के भांबरी युगल मुकाबले में हारे

लंदन (ईएमएस)। भारत के युकी भांबरी और उनके जोड़ीदार फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी विंबलडन टेनिस के युगल मुकाबले में हार के साथ ही बाहर हो गये हैं। भांबरी और ओलिवेटी को दूस

ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद जगी बड़ी उम्मीद ,भारत-ब्रिटेन में फाइनल हो सकती है फ्री ट्रेड डील

लंदन(ईएमएस)। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है। कीर स्टार्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने डेविड लैमी को विदेश सचिव (विदेश मंत्री) बनाया है। वह भारत और ब्रिटेन के द्वीपक्षीय संबंधों पर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को दोस्त बताया और पिछले सप्ताह उन्होंने एक महीने के भीतर भारत दौरे की अपनी मंशा जाहिर की।

ब्रिटिश विदेश मंत्री डैविड लैमी पिछले सप्ताह लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने भारत दौरे की अपनी मंशा का खुलासा किया था। उनके विदेश मंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एज जयशंकर ने उन्हें बधाई भी दी और दोनों देशों के बीच इंगेजमेंट बढ़ाने और पार्टनर्शिप को मजबूत करने की बात कही।

दिवाली 2022 में ही फाइनल होनी थी डील

ब्रिटिश विदेश मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद डैविड लैमी ने कहा कि विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाना मेरे जीवन का सम्मान है। भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर बोरिस जॉनसन को घेरते हुए उन्होंने कहा था कि ट्रेड डील के बिना कई दिवाली आई और गई, कई बिजनेस इसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, यह ट्रेड डील जॉनसन के कार्यकाल से ही पेंडिंग है, जिन्होंने दिवाली 2022 तक इसे फाइनल करने का वादा किया था।

ब्रिटिश मंत्री ने भारतीय मंत्रियों से की ये अपील

ब्रिटिश मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था, (वित्त) मंत्री (निर्मला) सीतारमण और (ट्रेड) मंत्री (पीयूष) गोयल को मेरा संदेश है कि लेबर पार्टी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चलिए हम फाइनली फ्री ट्रेड डील को पूरा करते हैं। भारत को ब्रिटेन के लिए प्राथमिकता बताते हुए डैविड लैमी ने इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सुपरपावर बताया था।

ब्रिटिश मंत्री ने भारत को बताया महाशक्ति

डैविड लैमी ने अपने भाषण में कहा था, लेबर के साथ, बोरिस जॉनसन द्वारा एशिया में रुडयार्ड किपलिंग की उस पुरानी कविता को दोहराने के दिन खत्म हो गए हैं। अगर मैं भारत में कोई कविता सुनाऊंगा, तो वह टैगोर की होगी। क्योंकि भारत जैसी महाशक्ति के साथ सहयोग और सीखने के क्षेत्र असीमित हैं।

ब्रिटेन के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की

लंदन (ईएमएस)। ब्रिटेन के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए तैयार हैं। भारत और ब्रिटेन दो वर्षों से अधिक समय से एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में आम चुनावों के बीच 14वें दौर में वार्ता रुक गई थी। उम्मीद है कि अब स्टॉर्मर के नेतृत्व वाली नई लेबर सरकार फिर वार्ता शुरू करेगी।

नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री की हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय फोन वार्ता के संबंध में डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि शनिवार को सबसे पहले मोदी से बात हुई और उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया से बात की गई।

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ''दोनों नेताओं ने चुनावी जीत पर एक-दूसरे को बधाई दी और ब्रिटेन तथा भारत के बीच संबंधों की मजबूती पर विचार-विमर्श किया।''

देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 651.99 अरब डॉलर हुआ

मुंबई (ईएमएस)। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 जून को समाप्त सप्ताह में 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह कुल मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा था। इस साल सात जून को भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 28 जून को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.25 अरब डॉलर घटकर 572.88 अरब डॉलर रही। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 42.7 करोड़ डॉलर घटकर 56.53 अरब डॉलर रह गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 3.5 करोड़ डॉलर घटकर 18.01 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.57 अरब डॉलर रहा।

सरकार ने स्टील, एल्युमीनियम के बर्तनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने स्टेनलैस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बा ंआईएस) ने कहा ?कि यह फैसला उप भोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ?लिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइ ंआईटी) ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रसोई के इन बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया था। बीआईएस ने भारतीय मानक संस्थान (आईएस आई) चिह्न को निर्धारित किया है। यह उत्पाद की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का आश्वासन देता है। बीआईएस के अनुसार आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिह्न न हो। बयान में कहा गया ?कि आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम बीआईएस द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं। मानकों में सामग्री की आवश्यकताएं, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन मापदंड शामिल होते हैं।

मालदा का मशहूर आम विदेश में नहीं हुआ निर्यात.....जाने क्यों

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल के मालदा से आमों का निर्यात इस साल प्रभावित हुआ है, क्योंकि निर्यातक विदेशी खरीदारों से अच्छी कीमत हासिल करने में विफल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि विक्रेताओं को घरेलू बाजार में आकर्षक मूल्य मिल रहे हैं। ब्रिटेन और यूएई के आयातकों ने शुरू में रुचि दिखाई थी, हालांकि कीमत पर सहमति नहीं बनने के चलते निर्यात नहीं हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि दूसरी ओर विक्रेताओं को घरेलू बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली में एक प्रदर्शनी में लगभग 17 टन मालदा आम 100 रुपये से 150 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिका। कम फसल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के कारण थोक कीमतों में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मालदा के बागवानी उपनिदेशक सामंत लायेक ने बताया कि इस साल, ब्रिटेन और दुबई के खरीदारों ने निर्यात सौदे रद्द कर दिए, जिन्होंने शुरू में रुचि दिखाई थी। हम जो दाम मांग रहे थे, वे उसे पूरा नहीं कर सके।

पहले चरण में हिमसागर किस्म के 13 क्विंटल निर्यात के लिए कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन आयातक बातचीत के अंतिम चरण में कीमत पर सहमत नहीं हो सके। इस साल गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में भारी गिरावट के कारण आम की कीमतें बढ़ गई हैं। मालदा में आम की कई किस्में उपलब्ध हैं, जैसे कि फाजली, हिमसागर, लक्ष्मणभोग, लंगड़ा और आम्रपल्ली।

भारत में निवेश न करने के फैसले से नुकसान में रहेगा टेस्ला: ओला कैब

- टेस्ला की आर्थिक चुनौतियों के कारण कंपनी भारत में और निवेश नहीं करेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। ओला कैब्स के एक व?रिष्ठ अ?धिकारी ने कहा ?कि भारतीय बाजार में निवेश न करने का टेस्ला का फैसला अमेरिका की इस कंपनी के लिए एक बड़ा नुकसान है। भारत के लिए नहीं। एक्स पर एक पोस्ट में अ?धिकारी ने कहा ?कि अगर यह सच है, तो यह टेस्ला का नुकसान है, भारत का नहीं। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और लिथियम का क्षेत्र अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब टेस्ला कुछ सालों बाद फिर से भारत को गंभीरता से देखेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों की पूछताछ का जवाब नहीं दिया है और अब उम्मीद नहीं है कि वह भारत में निवेश करेगी। यह खबर एलन मस्क के भारत दौरे को टालने के बाद आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला की आर्थिक चुनौतियों के कारण कंपनी भारत में और निवेश की योजना नहीं बना रही है। टेस्ला की ग्लोबल सेल्स इस तिमाही में लगातार दूसरी बार कम हुई है और उसे चीन से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने नौकरियों में कटौती की घोषणा की है, अपने मुख्य साइबरट्रक स्टॉल को बेच दिया है और मेक्सिको में अपने प्लांट के निर्माण को टाल दिया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अब सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों पर ध्यान दे सकती है। अप्रैल में मस्क ने भारत की यात्रा रद्द कर दी थी, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे। बताया जा रहा है कि यह यात्रा कंपनी में जरूरी कामों के कारण रद्द हुई। इस साल मार्च में, भारत सरकार ने 41.5 अरब रुपए (500 मिलियन डॉलर) की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में वैश्विक ईवी निवेश को आकर्षित करने और भारत को एडवांस ईवी के लिए एक बड़ा निर्माण केंद्र बनाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।

म्युचुअल फंड उद्योग का एयूएम 60 लाख करोड़ के पास पंहुचा

मुंबई (ईएमएस)। शेयर बाजारों की तेजी और जोरदार निवेश के बदौलत म्युचुअल फंड उद्योग की औसत तिमाही प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में लगातार दूसरी तिमाही (जून 2024) में करीब दो अंकों की वृद्धि हुई। औसत एयूएम 9 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2024 की पहली तिमाही के 54.1 लाख करोड़ से बढ़कर जून तिमाही में 59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एमफी) के आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली। पिछली तिमाही में क्रमिक आधार पर करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। फंडों की एयूएम में वृद्धि और बाजार की तेजी को मोटे तौर पर खुदरा निवेशकों से बल मिला है। शेयर बाजारों में उनका भरोसा बरकरार है जबकि कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आगे भी खुदरा निवेश मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

एयूएम में वृद्धि नए निवेश और पोर्टफोलियो में मौजूद परिसंपत्तियों में बढ़त पर निर्भर करती है। पिछली कुछ तिमाहियों में दोनों मोर्चे पर बढ़त काफी ज्यादा रही है। 2024 के पहले पांच महीने में ऐक्टिव इक्विटी योजनाओं ने औसतन करीब 25,000 करोड़ रुपए का मासिक निवेश हासिल किया है। कैलेंडर वर्ष 2023 में औसत शुद्ध निवेश महज 13,465 करोड़ रुपए रहा था। एयूएम में बढ़ोतरी को हाइब्रिड फंडों व पैसिव योजनाओं में नए निवेश से भी सहारा मिला है।

पैसिव फंडों (इनमें ईटीएफ, इंडेक्स फंड और ओवरसीज फंड शामिल) ने कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले पांच महीने में शुद्ध रूप से 52,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। पिछले साल 5,910 करोड़ रुपए के मुकाबले औसत मासिक निवेश 10,408 करोड़ रुपए रहा है। एसआईपी में मजबूत निवेश और ईपीएफओ व पेंशन फंडों से संस्थागत निवेश म्युचुअल फंडों और बाजार के लिए काफी मददगार रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग आश्वस्त हैं कि इन दोनों जरियों से उन्हें करीब 30,000 करोड़ रुपए का सकल निवेश हासिल होगा। पहले पांच महीनों में एसआईपी के द्वारा सकल एसआईपी निवेश करीब 1 लाख करोड़ रुपए रहा है। साल 2023 में कुल सकल निवेश 1.8 लाख करोड़ रुपए रहा था। इसके साथ ही बाजारों की तेजी ने भी एयूएम को मजबूती दी है।

सऊदी अरब ने किया नई वीजा सीरीज का ऐलान, घूमने की दी सुविधा

-भारतीय पर्यटक रियाद और जेद्दा और प्राचीन शहरों का कर सकेंगे भ्रमण

रियाद,(ईएमएस)। सऊदी अरब ने अब भारतीय यात्रियों को पर्यटक वीजा को नई वीजा सीराज देने का ऐलान किया है। इससे भारतीय आसानी से सऊदी का वीजा ले सकेंगे और वहां घूमने जा सकेंगे। सऊदी सरकार ने स्टॉपओवर वीजा, ई-वीजा सर्विस और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी है। इन वीजा से पर्यटक रियाद और जेद्दा जैसे शहरों के साथ ही लाल सागर और अल-उला जैसे प्राचीन शहर का भ्रमण करने जा सकेंगे। सऊदी सरकार ने नई गाइडलाइन और वीजा के विकल्प अलग-अलग तरह की यात्रा जरूरत को पूरा करने के मकसद से तैयार किए हैं ताकि पर्यटक सऊदी घूमने आ सकें।

इस समय मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता और कालीकट में दस वीजा सुविधा केंद्र हैं। दूसरे शहरों में भी ऐसे केंद्र बनाने की योजना है। यह सऊदी विजन 2030 के तहत है। इसका लक्ष्य 2030 तक 75 लाख भारतीय को सऊदी बुलाना है। सऊदी सरकार इस समय भारत को बड़े पर्यटक बाजार के रुप में देख रहा है। सऊदी सरकार ने 2024 के आखिर तक पर्यटकों की संख्या को दोगुना कर 22 लाख करने का लक्ष्य तय किया है।

भारतीय अब सऊदी के स्टॉपओवर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 96 घंटे तक के लिए वैध है और इसे प्रशासन और बीमा सेवाओं के लिए मामूली शुल्क पर सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर 90 दिन पहले लिया जा सकता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या किसी शेंगेन देश से वैध पर्यटक या व्यावसायिक वीजा रखने वाले भारतीय, प्रवेश के स्टांप प्रमाण के साथ ई-वीजा के लिए पात्र हैं। आधिकारिक पोर्टल के जरिए से प्रस्थान से पहले ई-वीजा लिया जा सकता है।

तूफान बेरिल से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित : संयुक्त राष्ट्र

जेनेवा (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि कैरिबियन में तूफान बेरिल से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने बताया कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में तूफान से लगभग 40 हजार, ग्रेनेडा में 1 लाख 10 हजार से ज्यादा और जमैका में 9 लाख 20 हजार लोग प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, तूफान बेरिल से अब तक करीब 11 लोगों की मौत हुई है। तूफान वर्तमान में बेलीज और मैक्सिको को प्रभावित कर रहा है। कैरियाकू 70 प्रतिशत और पेटिट मार्टिनिक में 97 प्रतिशत इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में यूनियन द्वीप पर 90 प्रतिशत घर प्रभावित हुए, जबकि कैनुआन द्वीप पर लगभग सभी इमारतों को नुकसान पहुंचा।

गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले.....87 लोगों की मौत

गाजा (ईएमएस)। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले 48 घंटों में इजरायली हमलों में करीब 87 लोगों केमारेजाने कीखबर है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायल के सैन्य हमले में करीब 38,098 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 87,705 अन्य घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पत्रकार अमजद जहजौह, उनकी पत्नी पत्रकार वफा अबू दबान और उनके बच्चे की नुसीरात शरणार्थी शिविर में इजरायली बमबारी में मौत हो गई है। जाहजौह और उसकी पत्नी की हत्या के साथ, 7 अक्टूबर को गाजा पर इजरायली युद्ध की शुरुआत के बाद से मारे गए फिलिस्तीनी पत्रकारों की संख्या 158 हो गई है।

गाजा में युद्ध विराम करने के लिए कतर में टीम भेजेगा इजरायल

यरूशलम,(ईएमएस)। गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल के मोसाद जासूसी एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया ने मध्यस्थों के साथ कतर के दोहा में एक बैठक की। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि बातचीत जारी रखने के लिए अगले सप्ताह एक टीम फिर से दोहा जाएगी। इजरायल के पीएमओ ने एक बयान में कहा कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बरकरार हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट में एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि एक अधिकारी ने कहा कि मोसाद अधिकारियों ने मध्यस्थों से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इजरायली कैबिनेट युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे में जब पूछा गया कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, तो सर्वे में शामिल 67 फीसदी लोगों ने कहा कि गाजा से बंधकों को वापस लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जबकि 26 फीसदी ने कहा कि गाजा में युद्ध जारी रहना चाहिए और 7 फीसदी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इस नौ महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के नए प्रयास का संकेत देता है। बता दें कि गाजा में अब तक 38,000 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनी की मौत हो चुकी है।

फ्रांस में रहस्मय तरीके से गायब हुई 1300 साल पुरानी तलवार

पेरिस (ईएमएस)। फ्रांस की प्राचीन तलवार 1300 साल के बाद अचानक गायब हो गई है। एक्सकैलिबर नाम की इस पौराणिक तलवार के दुनिया की सबसे तेज धार और कभी नष्ट ना होने वाली माना जाता है। यह तलवार 1300 वर्षों से ज्यादा समय से एक चट्टान में धंसी हुई थी। तलवार को किसने पत्थर से निकाला, इसकी कोई जानकारी अभी पुलिस को नहीं है। पुलिस हैरान है, क्योंकि तलवार जमीन से काफी ऊपर थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसा कहा जाता है कि ये तलवार एक वार में विशाल पत्थरों को भी काटने में सक्षम थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस डूरंडल तलवार को लोकप्रिय रूप से फ्रेंच एक्सकैलिबर के नाम से जाना जाता है। राजा आर्थर ने तसवार को पत्थर से निकाला था। किंवदंती के अनुसार, आठवीं शताब्दी में एक देवदूत ने रोमन सम्राट शारलेमेन को ये तलवार दी थी। जादुई तलवार और इससे जुड़ी किंवदंती फ्रांस के रोकैमडौर शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक थी। इस तलवार के बारे में शहर में कई कहानियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित बात ये है कि राजा शारलेमेन ने अपने बहादुर सैनिक रोलैंड को ये जादुई तलवार तोहफे में दी थी। युद्ध में घायल होने और अपनी मौत निश्चित देख रोलेंड ने इस तलवार को नष्ट करने का प्रयास किया ताकि उसके दुश्मन इसका इस्तेमाल ना कर सकें लेकिन तलवार को तोड़ने में असमर्थ रहे। इसके बाद हताशा में उन्होंने तलवार हवा में फेंकी और तलवार फ्रांसीसी शहर रोकामाडॉर में एक चट्टान पर जाकर धंस गई।

तलवार को देश दुनिया के लोग देखने आते थे और इसकी कहानियां सुनते थे। इस तलवार के अचानक गायब होने से लोग परेशान हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी नियति इस पौराणिक तलवार से जुड़ी हुई है। शहर के मेयर डोमिनिक लेनफैंट ने कहा कि निश्चित ही हम डूरंडल को बहुत याद करने वाले है। यह सदियों से रोकामाडॉर का हिस्सा रही है और शहर की पहचान की तरह थी। पुलिस ने कहा कि प्राचीन तलवार का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अफसर इससे हैरान है कि कोई चट्टान पर 100 फीट ऊपर चढ़ने और तलवार निकालने में कैसे सक्षम हो गया। स्थानीय लोग तलवार के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर कई तरह की बातें कर रहे हैं।

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, मंगल पर छिड़ेगी जंग, दुनिया का होगा अंत

लंदन (ईएमएस)। बुल्गारिया के बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उनमें से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला भी थी। साल 2023 में भी बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब उन्होंने एक बार फिर 2025 और आने वाले कुछ सालों की भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

बता दें कि वेंगेलिया पांडेवा गुशटेरोवा, जिन्हें बाबा वंगा के नाम से जाना जाता है, एक नेत्रहीन बल्गेरियाई रहस्यवादी व्यक्त थे, जिनकी मृत्यु 1996 में 85 वर्ष की आयु में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी दुनिया भर के लोग अभी भी उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन रखते हैं। बाल्कन के नास्त्रेदमस' कहे जाने वाले बाबा वेंगा ने दावा किया कि उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और फिर उनमें भविष्यवाणी करने का उपहार विकसित हुआ।

बाबा वेंगा की मुख्य भविष्यवाणियां

2025: यूरोप में एक बड़े संघर्ष के कारण महाद्वीप की जनसंख्या में कमी आएगी

2028: मानवता ऊर्जा के नए स्रोत खोजने के प्रयास में शुक्र ग्रह पर पहुंचेगी

2033: ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी

2076: साम्यवाद वैश्विक स्तर पर वापस आएगा

2130: अलौकिक सभ्यताओं से संपर्क होगा

2170: वैश्विक सूखा

3005: मंगल ग्रह पर युद्ध

3797: पृथ्वी का विनाश

5079: दुनिया का अंत

जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हराया

हरारे (ईएमएस)। जिम्बाब्वे ने पहले टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 13 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। यह इस साल भारत की पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय हार है। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 102 रन ही बना पाई और मैच हार गई। भारत के लिए इस मैच में आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। टीम इंडिया के लिए कप्तान शुभमन गिल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 31 रनों की पारी खेली। उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 27 तो आवेश खान ने 16 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा और तेंदई चतारा ने 3-3 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

इससे पहले, जिम्बाब्वे ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। और भारत को जीत के लिए 116 रनों का लक्ष्य दिया। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई। टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज क्लाइव मडांडे रहे, जिन्होंने नाबाद 29 रनों की पारी खेली। वहीं भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रवि बिश्नोई रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 13 रन देते हुए 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को 2, जबकि आवेश खान और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला।

ब्रिटेन के नए पीएम ने मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को किया शामिल

लंदन,(ईएमएस)। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया है। इस मंत्रिमंडल में एंजेला रेनर को डिप्टी पीएम और रेचल रीव्स को पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनाया है। स्टारमर के मंत्रिमंडल में 25 सदस्यों की टीम में 11 महिलाओं को भी शामिल किया है। नए मंत्रिमंडल में यवेट कूपर को गृह मंत्री, डेविड लैमी को विदेश मंत्री और जॉन हीली को रक्षा मंत्री बनाया गया है।

मंत्रिमंडल में शबाना महमूद को न्याय मंत्री, वेस स्ट्रीटिंग को स्वास्थ्य, ब्रिजेट फिलिप्सन को शिक्षा और एड मिलिबैंड को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। ब्रिटेनपीएमके रूप में अपने पहले भाषण में कीर स्टारमरने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पटरीपरलाने,ब्रिटिश सीमाओं को सुरक्षित करने और स्कूलों और किफायती घरों की जरुरत को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने बदलाव और राजनीति को सार्वजनिक सेवामें वापस लाने के लिए लोगों ने निर्णायक रूप से मतदान किया है।

स्टारमर ने कहा कि देश को बदलना स्विच दबाने जैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि दुनिया अस्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि बदलाव का काम तुरंत शुरू होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा, तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे नहीं, इसलिए मेरी सरकार तब तक लड़ेगी जब तक आप यह नहीं कहते कि देश आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा।

तालिबान ने अमेरिका के सामने रखी शर्त, दो के बदले मांगी दो की रिहाई

काबुल,(ईएमएस)। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने फिर अमेरिका आंख दिखाई है। अब तालिबान ने अफगान जेल में बंद दो अमेरिकी नागरिकों के बदले अपने दो नागरिकों की रिहाई की शर्त जो अमेरिका की बाइडेन सरकार के सामने रख दी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी जेल में दो अमेरिकी नागरिक बंद है और जिस तरह से अमेरिका अपने नागरिकों की रिहाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इस तरह से अफगानिस्तान सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा और रिहाई चाहती है। उन्होंने दो अमेरिकी नागरिकों के बदले उनके अमेरिका जेल में बंद दो अफगानी नागरिकों की रिहाई की मांग की है।

तालिबान ने जिन दो अफगानी नागरिकों की रिहाई की मांग की है, उनमें से एक मोहम्मद रहीम अफगानी है और वह कुख्यात आतंकवादी संगठन और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन (जो मारा जा चुका है) का खास है। रहीम ओसामा का खास था संगठन ने उसे अलकायदा का सदस्य बनाया था, जिसमें अपने दुश्मनों पर प्रयोग करने और जैविक और रासायनिक हथियार बनाने की योजनाएं में शामिल था। रहीम अल जवाहरी का भी बेहद करीबी था।

रहीम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सहयोग से अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह ग्वांतानामो जेल में बंद है। तालिबान सरकार द्वारा की इस मांग के बाद माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन अलकायदा का नियंत्रण फिर बढ़ रहा है। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा की प्रशिक्षण शिविर अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में चल रहे हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार के एक मंत्री हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में है।

माना जा रहा है कि अलकायदा पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर दुनिया के सामने आना चाहता है और इसके लिए वह अपनी ताकत बढ़ा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा ने अनेक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठनों में भी अपनी घुसपैठ बनाई है और तालिबान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसादुद्दीन फितरत के साथ भी अलकायदा के अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। अब देखा है कि सुपरपॉवर कहे जाने वाला अमेरिका तालिबान सरकार की शर्त को मानता है या नहीं।

बेंगलुरु में भारत का साइबर सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को

नई दिल्ली (ईएमएस)। अग्रणी उद्यम पूंजी फर्म एक्सेल की ओर से 25 जुलाई को बेंगलुरु में भारत के सबसे बड़े साइबरसिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत में प्रारंभिक चरण के साइबरसिक्योरिटी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के सुरक्षा ऑपरेटर, सीआईएसओ और अन्य लोग शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को अपने साइबरसिक्योरिटी नवाचारों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, वही फोनपे, ग्रो, क्रेड और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां और टेक यूनिकॉर्न के सीआईएसओ के एक समूह के समक्ष अपनी खासियत बताने का भी अवसर होगा। एक्सेल के एक भागीदान ने कहा कि भारत में बड़ी सॉफ्टवेयर और उपभोक्ता कंपनियों की तेजी से वृद्धि के साथ, बढ़ते खतरों से निपटने में सुरक्षा टीमें भी अत्यधिक कुशल हो गई हैं। एक्सेल ने दुनिया भर में 50 से अधिक साइबरसिक्योरिटी कंपनियों की फंडिंग की है।

इनमें से कई कंपनियों के संस्थापक भारतीय मूल के हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इन कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा और सुरक्षा संचालन में एआई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनियों की अगली पीढ़ी का नि

अयोध्या की तरह गुजरात में चुनाव जीतकर कांग्रेस करेगी नई शुरुआत

बीजेपी ने हमें धमकी देकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है

अहमदाबाद, ०६ जुलाई ।

सांसद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने हमें धमकी देकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है। मैं आपको बता दूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को तोड़नेजारहे हैं जैसे उन्होंने हमारे कार्यालयकोनुकसान पहुंचाया है। यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और भाजपा को गुजरात में हराएगी जैसा हमने अयोध्या में किया था।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार गुजरात में इस बार चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में शनिवार को अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव में गुजरात में भाजपा को उसी तरह हराएगी, जैसे उसने लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हराया है।

सांसद राहुल ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा, ''बीजेपी ने हमें धमकी देकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है। मैं आपको बता दूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है। यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और भाजपा को गुजरात में हराएगी, जैसा हमने अयोध्या में किया था।''

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीतेगी और यहीं से पार्टी फिर से एक नई शुरुआत करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी २ जुलाई को अहमदाबाद के पालदी इलाके में कांग्रेस के राज्य मुख्यालय के बाहर कांग्रेस-भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का जिक्र किया।

कांग्रेस-भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस झड़प में एक सहायक पुलिस आयुक्त सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा की हार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या में ही आती है।

उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों को उस समय गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि राम मंदिर समारोह में एक भी स्थानीय आदमी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। राहुल ने कहा, ''मुझे अयोध्या के सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं, बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। अयोध्या में तीन बार सर्वे कराया गया, लेकिन सर्वे वालों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ेगें तो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़े, लेकिन वहां से भी वो जान बचाकर निकले हैं।''

१८ रेलवे स्टेशनों, ७ कार्यालय भवनों पर सौर ऊर्जा से बचाए २७ लाख

राजकोट मंडल के विभिन्न १८ रेलवे स्टेशनों और ७ कार्यालय भवनों में ५१९ किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए

अहमदाबाद, ०६ जुलाई ।

रेल मंडल के १८ स्टेशनों और ७ कार्यालय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र के उपयोग से एक साल में २७.१८ लाख रुपए की बचत हुई है। वर्ष २०२३-२४ में इन सौर संयंत्रों से ४,५४ लाख यूनिट से ज्यादा हरित ऊर्जा उत्पन्न की गई।

सौर संयंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा की लागत की तुलना में विद्युत बोर्डों की ओर से आपूर्ति की गई ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत में अंतर के कारण बिजली बिल पर २७.१८ लाख रुपए की बचत हुई। पश्चिम रेलवे का राजकोट मंडल हरित और स्वच्छ रेलवे की दिशा में बड़े कदम बढ़ा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार तथा वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर रजनी यादव के मार्गदर्शन में मंडल की ओर से प्रदूषण रोकने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में राजकोट मंडल के विभिन्न १८ रेलवे स्टेशनों और ७ कार्यालय भवनों में ५१९ किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही और अधिक स्टेशनों एवं कार्यालयों पर सौर संयंत्र का प्रावधान किया जा रहा है। सौर संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके चलते बिजली बिलों में बचत भी हो रही है। राजकोट मंडल ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है।

छोटे स्टेशनों पर सौर संयंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग स्टेशनों पर बिजली के उपकरणों जैसे लाइटें, पंखे, कंप्यूटर और यहां तक कि सर्कुलेटिंग एरिया में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है। प्रमुख स्टेशनों पर उत्पन्न ऊर्जा बिजली ग्रिड को ट्रांसमिट की जाती है और बिजली बिल मीटर बिलिंग सिस्टम के मार्फत प्राप्त किए जाते हैं।

राजकोट मंडल में अमृत भारत कार्य के तहत १५ स्टेशनों पर बिजली विभाग से संबन्धित कार्य प्रगति पर हैं जिसमें मुख्यतया प्रकाश तीव्रता में बढ़ोतरी करना, वेटिंग हॉल में वातानुकूलित यंत्र (एसी) और लिफ्ट का प्रावधान करना इत्यादि कार्य शामिल है।

-: लोगों के लिए-लोगों के साथ-लोगों के बीच सरकार :-

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का नूतन जनकल्याण दृष्टिकोण

गांधीनगर 07 जुलाई, 2024 : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुदूरवर्ती-आंतरिक क्षेत्रों में बसने वाले लोगों तक बुनियादी एवं नागरिकोन्मुखी सेवा-सुविधा का वितरण सुनिश्चित करने के लिए ''लोगों के लिए, लोगों के साथ, लोगों के बीच सरकार'' का राज्य शासन का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री प्रेरित इस प्रो पीपल-प्रो एक्टिव गवर्नेंस के प्रेरक दृष्टांत में राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर व विकास अधिकारी अपने जिले में स्थित किसी एक तहसील के एक गाँव का औचक दौरा कर यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को मिलने वाली सेवाएँ-सुविधाएँ समय पर तथा सुचारु ढंग से मिल रही हैं या नहीं।

इस नतून जन हितकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पेटल के दिशानिर्देशानुसार दाहोद से द्वारका एवं अंबाजी से आहवा सहित समग्र राज्य के 33 जिलों के कलेक्टरों तथा जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) को एक-एक गाँव का अप्रत्याशित दौरा करने का निर्देश दिया गया था।

तद्अनुसार; शनिवार 6 जुलाई को सुबह से ही अधिकारी अपने जिले में किसी की एक तहसील के एक गाँव के दौरे पर पहुँचे। उन्होंने उन गाँवों में यह जाँच की कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, आँगनबाड़ी, केन्द्र तथा राज्य सरकार की राशन की दुकानों से खाद्यान्न वितरण, मध्याह्न भोजन, दूध संजीवनी योजना, भारतनेट कनेक्शन तथा बैंकिंग सेवाओं सहित बुनियादी सुविधा उचित ढंग से उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने इन सेवा-सुविधाओं में त्रुटि या कमी जैसी बातों की गहराई से समीक्षा की और पूरा विवरण प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जब तक किसी भी विषय को समग्र रूप से न देखा जा जाए, तब तक ऐसे विषय छोटे-मोटे, इक्का-दुक्का तथा छिटपुट ही नजर आते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने नूतन प्रशासनिक दृष्टिकोण अपना कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फील्ड अधिकारियों के जरिए लोगों तक जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसकी समीक्षा एवं आकस्मिक निरीक्षण का पीपल सेंट्रिक रवैया अपनाया है।

राज्य के मुख्य सचिव श्री राज कुमार के मार्गदर्शन में इसके लिए जिला कलेक्टरों तथा जिला विकास अधिकारियों को निर्धारित चेक लिस्ट फॉर्म देकर उसमें समीक्षा तथा निरीक्षण मूल्यांकन भरने को कहा गया था।

इस चेक लिस्ट फॉर्म में स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, दवाइयों के भंडार, डॉक्टर, स्टाफ नर्स आदि के विवरण, विद्यालय परिसर से जुड़े विषय, स्मार्ट क्लास, विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता, आँगनबाड़ी को मिलने वाली ढाँचागत सुविधा तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राहक भंडार से दिए जाने वाले अंत्योदय एवं अन्य योजनाओं के खाद्यान्न वितरण, ग्रामीण बैंकिंग सुविधा आदि के विवरण को विस्तार से एकत्र कर भरा गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न जिलों के गाँवों में सेवा-सुविधाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए गए जिला अधिकारियों के साथ बातचीत कर उनके अभिप्राय प्राप्त किए।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने स्थल पर उपस्थित ग्रामीण जनों के साथ भी सीधा व सहज संवाद कर उनसे पूछा कि सरकारी योजनाएँ व सुविधाएँ उन तक सुचारु ढंग से पहुँच रही हैं या नहीं। श्री पटेल ने जिला प्रशासकों को इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

मुख्य सचिव श्री राज कुमार ने खेडा, डांग, देवभूमि द्वारका, नर्मदा, छोटा उदेपुर, कच्छ, गीर सोमनाथ, पाटण, वडोदरा जिलों के कलेक्टरों तथा डीडीओ के साथ बातचीत कर उनके फील्ड विजिट के दौरान हुए कार्य निरीक्षण की जानकारी प्राप्त की।

मुख्य सचिव ने कलेक्टर-डीडीओ को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया कि अधिकारी आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए उनके जिलों में लोगों के बीच जाकर तहसील व ग्रामीण स्तर से भी फीडबैक लें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में कलेक्टर-डीडीओ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के कामकाज का नेतृत्व करें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल स्वयं भी जब जिलों के दौरे पर जाते हैं, तब सरकारी कार्यालयों का औचक दौरा कर लोगों से बातचीत कर यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सरकारी कार्यालयों के कामकाज से लोगों को संतोष है या नहीं, उन्हें कोई दुविधा तो नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टरों तथा डीडीओ को गाँवों के आकस्मिक दौरे पर भेज कर संवेदनशील एवं दृढ़ निर्णायकर्ता के रूप में राज्य के समग्र प्रशासन को अधिकाधिक लोकाभिमुख बनाने का एक नूतन प्रयोग प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा में मुख्य सचिव श्री राज कुमार, सम्बद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विभागों से जुड़ी सेवा-सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की।

केन्द्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी : अमित शाह

गांधीनगर, 6 जुलाई । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में कहा कि सहकारी संस्थाओं को देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ बनाया जाएगा। इसके जरिए देश के करोड़ों गरीब लोगों के जीवन में सुविधाओं, समृद्धि और आत्मविश्वास स्थापित करने का काम किया जाएगा।

केन्द्रीयगृहमंत्री शाह ने कहा कि भारत में सहकार कोई नया विचार नहीं है। हमलोगों के पूर्वजों ने 125 साल पुराने इस विचार को अपनाया था। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, गाडगिल, वैकुंठ मेहता और त्रिभुवन दास पटेल जैसे महान विभूतियों नेइसकी शुरुआत की थी। आज सहकारी आंदोलन देश के विभिन्न क्षेत्रोंमें बड़ा योगदान दे रहा है। सहकारी क्षेत्र कृषि लोन में 20 फीसदी,खाद के वितरण में 35 फीसदी, उत्पादन में 21फीसदी, चीनी उत्पादन में 31फीसदी,गेहूं की खरीदी में 13 फीसदी, धान की खरीदी में 20 फीसदी योगदान दे रहा है। शाह ने कहा कि आगामी5साल में सहकारिता का इतना मजबूत पीलर खड़ा करना है जिससे आगामी 125 साल तक सभीगांवों और घरों तक सहकारिता का लाभपहुंच सके। उन्होंने कहा किसरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से दो नई योजनाएं लेकर आई है। इथेनॉल को बढ़ावा देने और मक्का उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था की है कि सरकार की दो बड़ी सहकारी समितियां किसानों द्वारा उत्पादित मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ऑनलाइन खरीदेंगी और उससे इथेनॉल का उत्पादन करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसान समृद्ध होंगे बल्कि पेट्रोल आयात कम करके देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह अब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और उपभोक्ता सहकारी संगठन भी 4 प्रकारकीदालें100प्रतिशत एम एसपी पर खरीदेंगे। उन्होंने कहा, हमें सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम सहकारी क्षेत्र के सभी आर्थिक लेन-देन सहकारी क्षेत्र के भीतर ही करें तो हमें सहकारी क्षेत्र के बाहर से एक पैसा भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) और देश भर के सभी राज्य सहकारी बैंकों से अनुरोध किया कि प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)और अन्य सहकारी संस्थाएं अपना खाता जिला सहकारी बैंक या स्टेट को- ऑपरेटिव बैंक में खोले, जिससे न केवल सहकारी क्षेत्र मजबूत होगाबल्किपूंजी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। शाह नेप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 साल के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विवरण भी दिया। शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनबहु-राज्यसहकारी संस्था-जैविक समिति, निर्यात समिति और बीज समिति का भी गठन किया है, जिससे किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी।

शाह ने कहा कि देश में 1100 नए किसान उत्पादकसंगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं, 1 लाख से अधिक पैक्स ने नए बाइलॉज को स्वीकार कर लिया है और अब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 2,000 करोड़ रुपये का बांड जारी करने से यह संगठन अधिक सहकारी समितियों के कल्याण के लिए काम करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ खोलने का लक्ष्य मिला है, सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है, आयकर लाभ और नकद निकासी सीमा दोनों बढ़ा दी गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाकर सहकारी चीनी मिलों के लिए 15,000 करोड़ का आयकर देनदारी समाप्त किया है, जो आईटी देनदारी कई वर्षों से लंबित थी। इससे पूर्व शाह ने कहा कि आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को स्वतंत्र मंत्रालय बनाया था। शाह ने कहा कि आज गुजरात सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए नैनो-यूरिया और नैनो डीएपी पर 50 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की है।

अहमदाबाद में 147वीं रथ यात्रा आज

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर में कल भगवान जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक 147वीं रथ यात्रा निकलेगी भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा जी और बलभद्र जी के साथ रथों में सवार होकर नगरवासियों को दर्शन देने निकलेंगे रथ यात्रा को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं रथ यात्रा की सुरक्षा में पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया हैं साथ ही इस बार रथ यात्रा में उन्नत तकनीक और मानव संसाधनों का उपयोग किया जाएगा अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी इससे पहले प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ जी की मंगला आरती होगी, जिसमें केन्द्रीय मंत्री अमित शाह सपरिवार शामिल होंगे जिसके पश्चात भगवान की आंखों पर बंधी पट्टी खोली जाएगी और उन्हें खीचड़ी का भोग लगाया जाएगा बाद में भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और बलभद्र जी को तीन अलग अलग रथों में बिठाया जाएगा भगवान के रथ में सवार होने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सोने की झाड़ू से रथ यात्रा के मार्ग की सफाई करेंगे, जिसे पहिंध रस्म कहा जाता है और रथ यात्रा का प्रस्थान कराएंगे जमालपुर स्थित मंदिर से रथयात्रा में अखाडे, भजन मंडलियां, देश के विभिन्न राज्यों से आए साधु-संतों के समूह और 100 से भी अधिक ट्रक शामिल होंगे रथ यात्रा को लेकर पूरे शहरवासियों में जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा हैं विभिन्न ट्रकों में आकर्षक झांकिया बनाई गई हैं रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मूंग और जामून समेत अन्य प्रसाद वितरित किया जाएगा रथ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की आज समीक्षा की बाद में मीडिया से बातचीत में हर्ष संघवी ने बताया कि शहर में रथ यात्रा की पूर्व तैयारी के तहत राज्य के डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ रूट की समीक्षा की गई हैं कल रथ यात्रा शुरू होगी और भगवान लोगों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबर्दस्त उत्साह हैं इस बड़े और पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किये गये हैं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि इस बार उन्नत तकनीक और मानव संसाधनों का उपयोग किया गया हैं रथ यात्रा के दिन लाखों लोग दर्शन के लिए सड़क पर आते हैं, इसलिए लोगों ने खुद ही पीपीपी आधार पर दुकानों और अन्य स्थानों पर करीब 1400 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं साथ ही 20 ड्रोन से निगरानी की जाएगी रथयात्रा में पर्याप्त मॉनिटरिंग प्रबंधन का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 47 लोकेशन्स से 96 कैमरा, 20 ड्रोन, 1733 बॉडीवॉर्न कैमरा द्वारा लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। रथयात्रा को सफल बनाने के लिए आईजी स्तर से लेकर पुलिस कर्मचारियों तक 18700 से अधिक सुरक्षा कर्मचारी डयूटी पर तैनात रहेंगे। रथयात्रा में शामिल होने वाले रथों, ट्रकों, अखाड़ों, भजन मंडलियों तथा महंतों की सुरक्षा के लिए रथयात्रा के साथ मूविंगबंदोबस्त में लगभग 4500 पुलिस कर्मचारी जुड़ेंगे। समग्र रथयात्रा मेंबाधाके निवारण तथा सुचारु यातायात संचालन के लिए यातायात शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 1931जवान तैनात रहेंगे। इतन ही नहीं; लगभग16 क्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कोट क्षेत्र में खतरनाक मकानों पर बोर्ड लगा दिये गये हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि वे जर्जर इमारतों के नीचे या छत पर न खड़े हों।

राहुल गांधी को यह भी पता नहीं 'मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है उदघाटन नहीं': स्वास्थ्य मंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे को लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमा गया हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर गुजरात भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी पता नहीं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उदघाटन नहीं ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन राहुल गांधी के कांग्रेस सरकार बनाने के दावे खोखले साबित होने वाले हैं

रथयात्रा की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भगवान जगन्नाथजी की पूजा-आरती में सहभागी हुए

- भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों की सुख-शांति एवं समृद्धि बढ़े; इसके लिए भगवान जगन्नाथजी के चरणों में प्रार्थना की

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथजी की अहमदाबाद में आयोजित होने वाली 147वीं रथयात्रा की पूर्व संध्या पर जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना तथा संध्या आरती में सहभागी हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथजी के दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की। पूजा-अर्चना तथा संध्या आरती करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह परंपरागत रथयात्रा समाज के सभी वर्गों का सामाजिक समरसता उत्सव बन गई है। रविवार आषाढ़ी दूज के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्राजी तथा भाई बलभद्रज रथ में बैठ कर नगरचर्या को निकलने वाले हैं और स्वयं चल कर लोगों को दर्शन देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारी संस्कृति तथा परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अहमदाबाद शहर में जब रथयात्रा निकलने जा रही है, तब रथयात्रा के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ।'' उन्होंने कहा, ''रथयात्रा के लिए सभी का उत्सव सदा-सर्वदा बना रहे और राज्य के नागरिकों की सुख-शांति व समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे, भगवान जगन्नाथजी की कृपा गुजरात व समग्र देश पर सदैव बरसती रहे और इस वर्ष अच्छी वर्षा हो एवं किसान आनंद में रहें, इसके लिए मैंने भगवान जगन्नाथजी के चरणों में प्रार्थना की है।'' मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प विकसित गुजरात के माध्यम से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, सांसद दिनेश मकवाणा, शहर के विधायक, शहर पुलिस आयुक्त सहित बड़ी संख्या में नगरजन उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट का आवंटित जमीन ग्रामीणों को लौटाने राज्य सरकार को आदेश

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले से उद्योगपति गौतम अदाणी को बड़ा झटका लगा हैं हाईकोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट के निकट अदाणी को आवंटित की गई जमीन ग्रामीणों को लौटाने का गुजरात सरकार को आदेश दिया हैं अपना फैसले देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गौचर जमीन का मालिकाना हक सरकार का नहीं बल्कि जनता का हैं दरअसल गुजरात सरकार ने वर्ष 2005 में स्पेशल जोन और मुंद्रा पोर्ट को नवीनाल गांव की करीब 276 एकड़ जमीन आवंटित की थीं वर्ष 2011 में मुंद्रा के नवीनाल गांव के 12 लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और अदाणी को आवंटित जमीन वापस दिलाने की मांग करते हुए बताया कि वह जमीन गौचर की थीं

राहुल गांधी के अहमदाबाद आगमन पर विहिप का विरोध प्रदर्शन, दर्जनों कार्यकर्ता हिरासत में

अहमदाबाद, 6 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को पालडी स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव गांधी भवन के समीप प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिन्दू संबंधी कथित बयान को लेकर विहिप कार्यकर्ता नाराज हैं। विरोध प्रदर्शन में कई संत-महंत और महामंडलेश्वर भी शामिल हुए।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहमदाबाद आगमन को लेकर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पालडी में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में विहिप कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज के विरुद्ध संसद में गलत टिप्पणी की है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जब भी वे गुजरात आएंगे उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा।

प्रदर्शन में शामिल चैतन्य शंभु महाराज ने कहा कि राहुल गांधी के संसद में दिए बयान के विरोध में समग्र हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। सभी कार्यकर्ता साधु-संत इसमें शामिल हुए हैं। राहुल गांधी के अंदर जो हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना निहित है, उसे उन्होंने लोकसभा के अंदर उजागर किया है। इसका विरोध करने हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीरज बडगुजर ने कहा कि सुबह से ही पुलिस बंदोबस्त किया गया और नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी से भेंट की

भुवनेश्वर, 6 जुलाई

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने ओडिशा के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी से भेंट कर उन्हें नई सरकार के गठन पर बधाई दी तथा राज्य के जारी एवं भावी विकास के बारे में चर्चा की।

इस मुलाकात के दौरान श्री अग्रवाल ने ओडिशा के विकास हेतु वेदांता ग्रुप की अडिग प्रतिबद्धता को दोहराया। यह चर्चा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर केन्द्रित थी जो ओडिशा की परिवर्तनकारी यात्रा को और तेज़ कर सकें तथा राज्य के औद्योगिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएं।

नई सरकार के विज़न एवं नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा, ''ओडिशा की उल्लेखनीय वृद्धि इसके लोगों के अथक परिश्रम और अटूट समर्पण की परिचायक है। वेदांता की सफलता में ओडिशा की प्रमुख भूमिका है और इस प्रदेश के सतत एवं समावेशी विकास के लिए हम समर्पित हैं। श्री माझी के साथ मेरी मुलाकात बहुत उत्पादक रही और हमने ओडिशा की वृद्धि के लिए अपने साझा विज़न पर चर्चा की। उनके सक्षम नेतृत्व में हमारी दीर्घकालिक सहभागिता जारी रहेगी और हम ओडिशा को नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगे।''

एशियन ग्रेनिटो ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रीमियम एक्सपीरियंस गैलरी का अनावरण किया

अहमदाबाद,5 जुलाई

टाइल्स, मार्बल्स, क्वार्ट्ज और बाथवेयर सॉल्यूशंस ब्रांड जैसे लक्जरी सरफेस प्रोडक्ट्स में अग्रणी ब्रांड एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड (एजीएल) ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रीमियम एक्सपीरियंस गैलरी का उद्घाटन किया है। रणनीतिक रूप से आगमन क्षेत्र में स्थित, यह अनूठी मार्केटिंग पहल उद्योग में एक नया मानक स्थापित करती है।

एक्सपीरियंस गैलरी का उद्घाटन 29 जून 2024 को डिरेक्टर श्री भावेश पटेल, एसोसिएट डिरेक्टर श्री शौनक पटेल, सीओओ – बाथवेयर श्री पार्थिव दवे और एसोसिएट डिरेक्टर श्री केएम पटेल द्वारा अहमदाबाद हवाई अड्डे के वरिष्ठ अधिकारियों और एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड की वरिष्ठ नेतृत्व टीम की उपस्थिति में किया गया। यह अनूठी मार्केटिंग पहल, उद्योग के साथियों के बीच अद्वितीय विलासिता और अत्याधुनिक उत्पाद अनुभव की शुरुआत करती है, जो तुरंत पूरे उद्योग समुदाय, डिजाइनरों और घर मालिकों को समान रूप से आकर्षित करती है।

इस अवसर पर एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री कमलेश पटेल ने कहा, ''अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रीमियम एक्सपीरियंस गैलरी नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। हम अपने ग्राहकों और उद्योग भागीदारों को ऐसे गहन वातावरण में एजीएल उत्पादों की गुणवत्ता और विलासिता पर प्रत्यक्ष नज़र डालने के लिए उत्साहित हैं। ''

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बॉनस इश्यू लाने की योजना

19 जुलाई को होनेवाली बॉर्ड मीटिंग में बॉनस इश्यू और अधिकृत शेयर पूंजी बढाने को मंजूरी दी जाएगी; 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की आय रू. 89.87 करोड रही

सुरत, 6 जुलाई, 2024 - भारत में एयरेटेड ऑटोक्लेव्ड कोंक्रीट (एएसी) ब्लॉक,ब्रिक्स और पैनल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेडबोनस इश्यू पर विचार कर रही है। कंपनी के बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार,19 जुलाई 2024 को होने वाली है,जिसमें नियामक और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन बोनस शेयरों और कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। कंपनी की वर्तमान शेयर पूंजी रु. 14.14 करोड़ है जो रु. 2 अंकित मूल्य के 7.07 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी का रिजर्व और सरप्लस रु. 89.87 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने बिक्री में 19% और शुद्ध लाभ में 80% से अधिक की 5 साल की सीएजीआर साथ एक मजबूत परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और शेयरधारक मूल्य प्रद